checkup of all children attending special schools, introduction of appropriate vocational stream in the special schools, proactive role by trade unions in the elimination of child labour and effective enforcement of child labour related laws in the child labour endemic areas.

(c) and (d) Government is committed to the goal of eradication of child labour in all its forms. However, the rehabilitation child labour working in hazardous occupations has been taken up in the first instance. National Child Labour Projects have been set up in the child labour endemic states for the rehabilitation of children working in hazardous' occupations. So far a child labour projects have been set up for the rehabilitation of around 1.5 lakh children. These child labour projects are located in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamilnadu, Uttar Pradesh and West Bengal. As per the available information, around 1.05 lakh children are already enrolled in the special schools under the projects.

System of secret ballot for determining collective bargaining agency

1592. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government had committed through common Minimum Programme that Government for the purpose of determining collective bargaining agency would introduce the system of secret ballot;

(b) if so, the steps taken so far to implement the secret ballot; and

(c) by when Government wishes to complete the process?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) Certain Central Trade Union Organisations submitted a memorandum to the Prime Minister urging the Government to frame suitable legislation for recognition of trade unions by Secret Ballot. The issue of determination of the representative character of Trade Unions by Secret Ballot has been referred to the Bipartite Committee constituted by ihe Ministry of Labour and consisting of representatives of employees and workers. Further course of action will depend on the recommendation of the committee.

देश में खनिज संपदा के लिए सर्वेक्षण

1593. **श्री अजीत जोगी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस.आई.) द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान देश में खनिज भंडार की कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से खनिज कहां-कहां पाए गए हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) देश में खनिजों की खोज और लाज के लिए विदेशी कंपनियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(घ) क्या सरकार बेशकीमती खनिजों के खनन का कार्य भी विदेशी कपंनियों को सौपने का विचार रखती है;

(ड) सरकार द्वारा आगामी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन खनिजों की खोज के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाने का विचार हैं,

(च) क्या इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को सौपने से पहले संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया था, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) और (ख) : जी हां , खनिजों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफ आई पी बी) ने खनन/धातु विज्ञान के क्षेत्र में निवेश के लिए 33 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है जिनमें से केन्द्र सरकार को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे के लिए 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) तथा खनन पट्टे (एमएल) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उनके अतंर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दिये जाते हैं। खनिज रियायतें देने के लिए संबधित राज्य सरकारों को आवेदन देने होते हैं जो खनिज रियायत अधिकार देने में सक्षम